विचार बिन्दु

जब तक भारत का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा तब तक हम यह नहीं कह सकते कि देश में स्वराज है। –मोरारजी देसाई

वहां और यहां!

मेरे साथ प्राय: यह होता है कि जब भी किसी और जगह कुछ देखता हूं, तुलना करने लगता हूं। केवल तुलना नहीं, यह भी कि अगर अच्छा देखता हूं तो सोचता हूं कि मेरे यहां ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो सोचता हूं कि हमने क्या किया है कि हम वैसी स्थितियों से मुक्त हैं। पिछले दिनों एक संक्षिप्त आनंद यात्रा पर विदेश जाना हुआ तो फिर ऐसा ही हुआ। हम लोग लगभग दस दिनों के लिए दुनिया के दो बड़े और नामी शहरों लंदन और पेरिस की यात्रा पर गए थे। इन दो शहरों के बहाने दो देशों की भी यात्रा हो गई। खूब आनंद रहा। घूमे–फिर और परिवार का दुर्लभ संग–साथ मिला।

लौट कर जब सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा की कुछ छवियां साझा की तो स्वभावत: बहुतों की प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हुईं। मैंने जब कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की तस्वीरें साझा कीं तो बहुतों ने लिखा कि हमारे अपने देश में तो इससे भी अच्छी बहुत सारी जगहें हैं। यह बात मैं ख़ुद अनगिनत बार लिख और कह चुका हूं। भारत का बहुत समृद्ध अतीत है और हमारे पास कला–संस्कृति–स्थापत्य सबकी अकूत संपदा है। बात यहां यह नहीं है कि उस देश का कोई स्थापत्य या कोई कला कृति उन्नीस है और हमारे पास जो है वह इक्कीस है। कोई तुलना न तो हो सकती है और न होनी चाहिए। हर कृति का, हर जगह का अपना वैशिष्ट्य होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। टेम्स नदी की गंगा से तुलना की ही क्यों जाए? शेक्सपियर की कालिदास से तुलना का कोई औचित्य है ही नहीं। ब्रॉडवे और यक्षगान दोनों परस्पर अतुलनीय हैं। सबकी अपनी–अपनी अहमियत है। लेकिन जिस बात की तरफ़ बार–बार मेरा ध्यान जाता रहा है वह यह है कि हम अपनी संपदा को वैसे देश–दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जैसे अन्य बहुत सारे देश कर सके हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों के संग्रहालयों को देखकर मैंने महसूस किया है कि हमारे पास जो है उसे दुनिया के सामने लाने के लिए और अधिक प्रयत्न करने हैं। मुझे बहुत बार इस बात से बड़ा कष्ट होता है कि हम बाह्य दुनिया की चीज़ों के बारे में जितना जानते हैं उसका एक छोटा–सा अंश भर भी अपने देश की चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। मुझे ग़लत न समझ लिया जाए, इसलिए यह बात साफ़ कर दूं कि बाह्य दुनिया की जिन चीज़ों के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं वे महत्वहीन नहीं हैं। अगर हम आयफ़िल टॉवर के बारे में जानते हैं, मिश्र के पिरामिड्स के बारे में जानते हैं, बीट्ल्स के संगीत के बारे में जानते हैं, अमरीका के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानते हैं, रूस के स्टेट हरमिटेज संग्रहालय या पेरिस के लूव्रम्यूज़ियम के बारे में जानते हैं तो ये सब जानने योग्य हैं और इन्हें जानना बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें से कुछ को देखने का हमें मौका मिलता है तो यह बहुत बड़ी बात है। ख़ुद मुझे लूव्र संग्रहालय में प्रवेश कर गर्व और आह्लाद की जो अनुभूति हुई, वह शब्दातीत है। लेकिन विचारणीय यह है कि हमने अपने संग्रहालयों या स्मारकों को वैसा बनाये रखने, दिखाने और आकर्षित करने वाला बनाने के लिए क्या प्रयास किए हैं? हममें से कितने लोग हैं जो देश के दस प्रसिद्ध और बड़े संग्रहालयों के नाम भी बता सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपने शहर या प्रांत से बाहर कहीं जाते हैं तो वहां के किसी संग्रहालय को देखना हमारी बकेट लिस्ट में प्राय: नहीं होता है! हममें से कितने हैं जिन्होंने अपने शहर के या उसके आस–पास के किसी संग्रहालय को ठीक से देखा है? जयपुर में एक बहुत समृद्ध संग्रहालय है – अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। राज्य के बहुत सारे ज़िलों में भी राजकीय संग्रहालय हैं। लेकिन क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सरकारी हैं, वे हमें आकर्षित नहीं करते हैं। एक रूखा–सूखा पन और उदासीनता उनका स्थायी भाव होता है। जो निजी संग्रहालय हैं उनकी स्थिति फिर भी थोड़ी बेहतर है। आप दुनिया के किसी बड़े संग्रहालय को देखें, उसकी व्यवस्थाओं को देखें, यह जानने का प्रयास करें कि लोग क्यों उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यह देखें–समझें कि कैसे वे अपने यहां प्रदर्शित सामग्री को हाइलाइट करते हैं, उसकी खूबियों को प्रभावशाली तरीके से सामने लाते हैं,तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मुझे बहुत बरस पहले का दुबई का एक अनुभव अनायास याद आ रहा है। दुबई के सन् 1787 में निर्मित अलफ़हिदी क़िले में स्थित सन् 1971 से बनवाया गया दुबई संग्रहालय वहां के प्रमुखतम आकर्षणों में से एक है। मैं जब इस सग्राहलय को देखने गया तो किसी स्कूल के कोई एक सौ बच्चे अपनी शिक्षिकाओं के साथ वहां घूम रहे थे। उन बच्चों की औसत आयु लगभग पांच वर्ष रही होगी। निश्चय ही वे बच्चे उस सग्रहालय को उस तरह नहीं देख रहे थे, जैसे मैं देख रहा था। लेकिन उन्हें वहां लाया जाना महत्वपूर्ण था। क्या हम ऐसा करते हैं? क्यों नहीं करते? और यह बात केवल संठाहालयों के बारे में नहीं है।

> **बार-बार घोषित किया जा रहा था कि क्रू के समय पर नहीं पहुंचने से प्रस्थान में विलंब हो रहा है। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। आखिरकार काफी विलंब के बाद ट्रेन रवाना हुई और हम अपने गंतव्य पर पहुंचे गए। बाद में यहां घर लौटकर मुझे पता चला कि हमारे बच्चों ने इस विलंब की शिकायत की और उन्हें वहां की रेल की तरफ से बाकायदा एक बड़ी राशि रिफंड के रूप में मिली। क्या हम अपने देश में ऐसी किसी व्यवस्था की कल्पना भी कर सकते हैं? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए?**

दूसरी जिस बात की तरफ़ मेरा ध्यान गया वह यह कि इन दोनों शहरों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और विकास पर खूब ध्यान दिया गया है। इन दोनों ही शहरों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहुत सुदृढ़ और समृद्ध है। हमने तमाम सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया। नगर बस सेवा और मेट्रो रेल सेवा दोनों ही का जाल पूरे शहर में बिछा हुआ है और आप बिना अधिक प्रतीक्षा के कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। ये सुविधाएं इतनी अधिक व्यापक और सुव्यवस्थित हैं कि लोगों को अपने वाहन या भारत की तरह किराये की टैक्सी (उबर ओला वगैरह) सेवाओं की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पेरिस में भूमिगत मेट्रो का जैसे जाल ही बिछा हुआ है। अगर इन देशों की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से हम अपने देश की तुलना करें तो मन खिन्न हो जाता है। हमने शायद इस तरफ ध्यान देना ज़रूरी ही नहीं समझा है कि हमारे नागरिकों को ऐसी किसी सुविधा की ज़रूरत भी है। हमारे शहरों पर लोगों और वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रैफ़िक जाम अपवाद न रहकर आम हो गए हैं, पार्किंग की समस्या विकराल होती जा रही है लेकिन हमारे यहां इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नज़र नहीं आते। कृपया यह न कहें कि हमारे पास साधनों का अभाव है। साधन हैं तो उन्हें वहां खपाया जाता है जहां उनकी बहुत कम ज़रूरत होती है। साधनों की बरबादी का एक छोटा–सा नमूना आए दिन अख़बारों में छपने वाले वे सरकारी विज्ञापन हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य नेताओं की छवियों को हमारे मनों पर स्थायी बनाना है।कभी सोचकर देखें, इन पर कितना धन खर्च होता है। क्या इस धन का कोई और बेहतर उपयोग नहीं हो सकता, जो हमारी सुविधाओं का विस्तार करे!

मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ हमारे शासन तंत्र के सोच में भी लगती है। एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूं। इन दिनों पढ़ने को मिल रहा है कि कर्नाटक सरकार ने लगभग एक सप्ताह पहले बेंगलुरु शहर में बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। इस रोक की वजह से वहां यातायात की समस्या जो पहले ही विकराल थी, अब और ज़्यादा विकट हो गई है। ऑटो और टैक्सी वाले मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं और सड़कें दो पहिया वाहनों की जगह चार पहिया वाहनों के बोझ तले कराह रही हैं। इस सरकारी हुक्म की वजह से दिन के सामान्य घण्टों में वहां ट्रैफ़िक की भीड़ 18 से 22 प्रतिशत तक बढ़ गई है। न केवल विद्यार्थियों और कम खर्च में अपने कार्य स्थल तक पहुंचने वाले कार्मिकों की ज़िंदगी दूभर हो गई है, लगभग छह लाख बाइक चालकों के सामने रोज़ी–रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। आप कोई व्यवस्था कर नहीं रहे और जो व्यवस्था चल रही है, उसे चलने नहीं देंगे। कैसी अजीब और मूर्खता की बात है। लेकिन है। अगर बाइक टैक्सी चालन में कुछ अनियमितताएं थीं तो उन्हें दूर करते।

एक और बात। हमें रेल से लंदन से पेरिस जाना था। टिकट वगैरह सब ले लिए थे। क्योंकि एक से दूसरे देश में जाना था इसलिए अन्य औपचारिकताएं भी पूरी हो गई थीं। लेकिन ट्रेन समय पर रवाना नहीं हुई। बार–बार घोषित किया जा रहा था कि क्रू के समय पर नहीं पहुंचने से प्रस्थान में विलंब हो रहा है। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। आखिरकार काफी विलंब के बाद ट्रेन रवाना हुई और हम अपने गंतव्य पर पहुंचे गए। बाद में यहां घर लौटकर मुझे पता चला कि हमारे बच्चों ने इस विलंब की शिकायत की और उन्हें वहां की रेल की तरफ से बाकायदा एक बड़ी राशि रिफंड के रूप में मिली। क्या हम अपने देश में ऐसी किसी व्यवस्था की कल्पना भी कर सकते हैं? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए?

इतना पर्याप्त नहीं है कि हम अपनी व्यवस्थाओं पर गर्व करते रहें और जैसा है वैसा चलता रहने दें। उसे बेहतर बनाने के प्रयास निरंतर करते रहने से और दूसरों को देखकर कुछ सीखने से ही बात बनेगी। फिलहाल इतना ही।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

सत्ता नहीं, सेवा का पखवाड़ा : पं. दीनदयाल से प्रेरित राजस्थान मॉडल

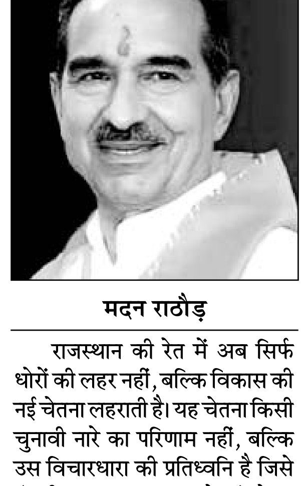

मदन राठौड़

राजस्थान की रेत में अब सिर्फ धोरों की लहर नहीं, बल्कि विकास की नई चेतना लहराती है। यह चेतना किसी चुनावी नारे का परिणाम नहीं, बल्कि उस विचारधारा की प्रतिध्वनि है जिसे पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के रूप में परिभाषित किया था–समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान का दर्शन। इसी दर्शन को राजस्थान की धरती पर सबसे पहले साकार करने का श्रेय जाता है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरोंसिंह शेखावत जी को, जिन्होंने वर्ष 1977–78 में "अंत्योदय योजना" की शुरुआत की। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे गरीब पांच परिवारों को चिन्हित कर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और स्वरोजगार के संसाधनों से जोड़ने का जो प्रयास किया, वह अंत्योदय को प्रशासनिक रूप देने वाला ऐतिहासिक कदम था। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार "पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा" का आयोजन कर रही है, तो यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण का उद्घोष है। यह पखवाड़ा समाज के उन वर्गों तक पहुंचने का प्रयास है, जिन्हें दशकों तक शासन की परिधि से बाहर रखा गया, जिनके नाम पर घोषणाएं तो हुईं लेकिन परिणाम धरातल पर नहीं उतरे।

24 जून से 9 जुलाई 2025 तक आयोजित इस पखवाड़े में राजस्थान सरकार खुद जनता के द्वार पर है–न फाइलों में उलझन, न दफ्तरों के चक्कर। प्रत्येक पंचायत में लगाए जा रहे सेवा शिविर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का लाभ केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि हाथों में नजर आए। भूमि सीमांकन, नामांतरण, रास्तों के प्रकरण, स्वामित्व पट्टे, जल कनेक्शन, बिजली के खंभों की मरम्मत, स्वास्थ्य कार्ड वितरण, खाद्य सुरक्षा के लंबित मामलों का निस्तारण, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, मृदा परीक्षण, पौध वितरण, पशुओं का टीकाकरण और बीमा–ये सब काम तेज़ी से, लोगों के द्वार पर किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार का दृष्टिकोण योजनाओं के प्रचार तक सीमित नहीं, बल्कि उनके प्रभावशाली और समयबद्ध क्रियान्वयन पर आधारित है। यह सरकार योजनाओं को सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन तक ले जाती है जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।

यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी आज गांव–गांव में सक्रिय है, और प्रत्येक परिवार को राज्य की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आज यह नया राजस्थान केवल राजधानी या जिला मुख्यालयों तक नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी बदलाव की मिसाल पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की गई है, जो प्रत्येक परिवार को गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही गरीब, श्रमिक और जरूरतमंद वर्ग के लिए गरिमापूर्ण भोजन की व्यवस्था श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से की गई है, जो मात्र कुछ रुपये में पौष्टिक और गरम भोजन सुलभ कराती है। सरकार की मंशा सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन देने की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र राजस्थान सरकार की प्रेरणा है, लेकिन राजस्थान ने इसे केवल नारा नहीं, जमीनी क्रांति का आधार बनाया है। केन्द्र सरकार की दिशा और सोच राज्य की कार्यक्षमता को मजबूती देती है, पर असली अंतर पैदा करती है राज्य सरकार की इच्छाशक्ति, कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक संवेदनशीलता। यह तथ्य आज स्पष्ट है कि भाजपा सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को व्यवहार में उतारा है। वर्षों तक गरीबों के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन गरीबी वहीं की वहीं रही। आज जब सरकार पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, तो यह स्पष्ट है कि शासन की नीयत बदली है और दृष्टि भी।

भाजपा का वैचारिक आधार "राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति अंतिम" अंत्योदय और एकात्म मानववाद से प्रेरित होकर समावेशी विकास की संकल्पना को मूर्त रूप देता है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने सरकारी तंत्र को केवल बजट खर्च करने की मशीन नहीं, बल्कि जनसेवा का जीवंत माध्यम बना दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पखवाड़े के उद्घाटन अवसर पर कहा था कि हमारा संकल्प है कि राजस्थान का हर गांव और हर परिवार समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। यह संकल्प अब केवल घोषणा नहीं, बल्कि धरातल पर उतरी हुई नीति बन चुकी है। जब सरकार की मंशा ईमानदार हो, दृष्टि स्पष्ट हो और कार्यप्रणाली पारदर्शी हो, तब प्रशासन केवल आदेशों का क्रियान्वयनकर्ता नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम बन जाता है। यही राजस्थान की नई पहचान है–एक ऐसा राज्य जो अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर आधुनिकता और समावेशी विकास की ओर दृढ़ता से अग्रसर है।

यह पखवाड़ा केवल योजनाओं का मेल नहीं, यह सामाजिक न्याय, गरिमा और आत्मनिर्भरता की पुनर्परिभाषा है। यह अंत्योदय के उस विचार का क्रियान्वयन है, जो दशकों तक पुस्तकों और भाषणों तक सीमित रहा। अब वह विचार घर–घर तक पहुंच रहा है और यही है राजस्थान की असली ताकत, यही है भाजपा सरकार का असली चरित्र।

मदन राठौड़
प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान

राजस्थान : कोचिंग तो 'उद्योग', स्कूल 'डमी', बातें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की

राजेन्द्र मोहन शर्मा

राजस्थान, एक ऐसा राज्य जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, रंग–बिरंगे परिदृश्यों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, आज एक नए परिदृश्य में उलझा हुआ है–कोचिंग उद्योग का तेजी से बढ़ता विस्तार। कोटा, जो कभी उद्योग नगरी के रूप में पहचाना जाता था, अब देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। लेकिन यह कोचिंग संस्कृति अब केवल कोटा तक सीमित नहीं है; यह जयपुर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर और राज्य के छोटे–बड़े शहरों में भी फल–फूल रही है। कोचिंग 'उद्योग' ने शिक्षा के पावन कार्य के बजाय इसे एक व्यवसाय का दर्जा दे कर समाज को काफी मुसीबत में डाल दिया है। आज सरकार की भी प्राथमिकता में बदलाव आ गया है है। यह स्थिति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, बल्कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संरचना और शिक्षा प्रणाली की नींव को भी हिला रही है। आश्चर्यजनक बात है कि कोचिंग को सरकार स्वयं उद्योग मानकर केंद्र और राज्य सरकारें इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही हैं। कोचिंग उद्योग की बढ़ती मांग और स्कूलों व सरकार की इन पर बढ़ती निर्भरता कई सवाल खड़े करती है। वह समय गुजरे बहुत अरसा नहीं हुआ है जब कोचिंग, ट्यूशन, पासबुक, कुंजी, वनवीक सीरीज से पढ़ना पढ़ाना पाप समझा जाता था, बाद में कानून अपराध घोषित हुआ और अब सरकारी छत्रछाया में यह सम्पूर्ण उद्योग बनकर फल–फूल रहा है।

तो क्या अरबों रूपये खर्च कर चलने वाले सरकारी गैर सरकारी स्कूल कालेज निकम्मे ओर नाकारा साबित हो चुके हैं, क्या इनमें पढ़ाने वाले शिक्षक अयोग्य हैं, क्या सरकार ने कोचिंग की बिमारी को जरूरी लाइसेंस दे दिया है। लगता तो यही है सरकार की सहमति से पनप रहा यह उद्योग सम्पूर्ण समाज में एक व्याधि की तरह व्याप्त हो गया है। स्लो पाइजनिंग का असर इतना गहरा है कि शिक्षक स्वयं बच्चों को कोचिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, अभिभावकों को इस कि सहायता के बिना अपने बच्चों की वैतरणी पार होती नजर नहीं आ रही और बच्चे घुण की तरह पिस रहे हैं। जब यह उद्योग है तो जाहिर है यहां से निकलने वाला प्रोडेक्ट भी इसी ट्रेढ का मार्का है। इसका आशय यह नही है कि ये प्रतिभाशाली बच्चे उचित दिशा में नहीं जा रहे लेकिन सोचिए ये ही वे बच्चे जरूर बन गए हैं जो संवेदना के स्तर पर काफी कमजोर और बाजार के लिए एक उपयोगी माल के रूप में उपस्थित हैं। कोटा, जिसे 'कोचिंग कैपिटल' के रूप में जाना जाता है, हर साल 1.5 से 2 लाख छात्रों को आकर्षित करता है, जो मेडिकल (NEET) और इंजीनियरिंग (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। इस शहर में बड़े कोचिंग संस्थान अपनी सफलता बाजे–गाजे बजा रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के मालिकों के यहां पड़ने वाले इन्कमटैक्स विभाग के छापों और उनसे निकले समाचारों से आपको इनकी काली पीली या लाल जो भी है उस कमाई का अनुमान हो सकता है। एक कोचिंग संस्थान मालिक ने तो हजारों करोड़ में विदेशों में होटल खरीद डालें हैं। तो जाहिर है कोटा अब केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं, बल्कि मानसिक दबाव और आत्महत्याओं का पर्याय बन गया है। 2023 में कोटा में 25 छात्रों ने आत्महत्या की, जो 2015 के बाद सबसे अधिक है, और 2025 में अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं। यह स्थिति कोटा शहर की छवि को धूमिल कर रही है। आपको पता है इस उद्योग का आर्थिक मूल्य लगभग 7,000 करोड़ रुपये वार्षिक का है। कोटा की अर्थव्यवस्था इस उद्योग पर निर्भर है, जिसमें 3,000 हॉस्टल, मेस, और अन्य सहायक सेवाएँ शामिल हैं। लेकिन हाल के वर्षों में, कोचिंग में छात्रों की संख्या में 30–35 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। क्योंकि अब अभिभावकों में बच्चों की आत्महत्या के मामलों से भय व्याप्त हो गया है।

यह कोचिंग संस्कृति अब कोटा से आगे बढ़कर जयपुर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, और भरतपुर जैसे शहरों में फैल रही है। जयपुर, राजधानी होने के नाते UPSC, RPSC, और अन्य सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए कोचिंग का केंद्र बन गया है। सीकर अब स्वयं एक कोचिंग हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ 130 से अधिक कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें 15 बड़े संस्थान शामिल हैं, और हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं। जोधपुर और उदयपुर में भी NEET, JEE, और UPSC की तैयारी के लिए बड़े कोचिंग संस्थान स्थापित हो चुके हैं।

उदयपुर में 100 और जोधपुर में 100 सीटें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत और के लिए निर्धारित की गई हैं। भरतपुर जैसे छोटे शहरों में भी कोचिंग सेंटरों की संख्या बढ़ रही है, जहाँ स्थानीय स्तर पर 20 सीटें इस योजना के तहत उपलब्ध हैं। इन शहरों में कोचिंग उद्योग का विस्तार और सरकार प्रायोजित व्यवस्था ने चिंता पैदा करदी है क्या हम स्कूलों को बंद होते देखना चाहते हैं। सरकार के समर्थन से उपजे और कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे ये कोचिंग संस्थान स्कूलों को निगल रहे हैं तभी तो डमी स्कूलों का प्रचलन हमारे सामने है। वैसे नाकारा स्कूल संचालकों का इसमें जाता क्या है उन्हें तो बैठे–बिठाए मोटा पैसा मिल ही रहा है। शिक्षा के इस पावन कार्य को उद्योग का दर्जा देना एक गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक दुरावस्था को दर्शाता है। शिक्षा, जो कभी ज्ञान, नैतिकता, और समग्र विकास का माध्यम थी, अब एक व्यावसायिक मॉडल में बदल गई है। कोचिंग संस्थानों को 'उद्योग' का दर्जा देना यह दर्शाता है कि शिक्षा अब केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय है। कोटा में यह उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, लेकिन यह शिक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोचिंग व्यवस्था को लेकर काफी किन्तु परन्तु लगे हुए हैं। शायद इसीलिए केंद्र सरकार इस उद्योग के नियमन के लिए समीक्षा कोचिंग के लिए बनाई गई नीतियों और गाइडलाइनों से स्पष्ट है। 2024 में, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का दाखिला रोकने और भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रावधान शामिल थे। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक–2025 में 16 वर्ष की उम्र सीमा को हटा दिया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह कोचिंग संस्थानों के दबाव में किया गया है। यह दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें कोचिंग को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में देख रही हैं, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी मांग को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं मानतीं।

इसके साथ ही डमी स्कूलों का बढ़ता चलन इस समस्या को और गंभीर बनाता है। ये स्कूल छात्रों को केवल नाममात्र के लिए पंजीकृत करते हैं, ताकि वे कोचिंग में पूरा समय दे सकें और बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो सकें। हाल ही में, ने राजस्थान और दिल्ली के 21 डमी स्कूलों की मान्यता रद्द की, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। राजस्थान के कोचिंग सेंटरों से निकलने वाले छात्रों में स्थानीय और बाहरी राज्यों के छात्रों का अनुपात भी विचारणीय है। कोटा में पढ़ने वाले छात्रों में लगभग 70–80 प्रतिशत बाहरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, और मध्य प्रदेश से आते हैं, जबकि राजस्थान के छात्रों का हिस्सा 20–30 है। जयपुर और सीकर में यह अनुपात थोड़ा अलग है, उदयपुर, जोधपुर, और भरतपुर जैसे शहरों में स्थानीय छात्रों की संख्या और भी अधिक है, क्योंकि ये शहर छोटे और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए कोचिंग को अधिक किफायती बनाते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो, SC, ST, OBC, और EWS वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है, ने भी स्थानीय छात्रों की भागीदारी बढ़ाई है। इस योजना के तहत जयपुर और कोटा में 250–250 सीटें, सीकर में 160, और जोधपुर व उदयपुर में 100–100 सीटें निर्धारित हैं।कोचिंग सेंटरों के भय से ठास्त स्कूल और सरकार भी अब पढ़ाई के बजाय कोचिंग पर जोर दे रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की बढ़ती मांग और स्कूलों की इन परीक्षाओं के लिए अपर्याप्त तैयारी है। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धित प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण अभिभावक और छात्र कोचिंग को प्राथमिकता देते हैं। सरकार भी इस मांग को स्वीकार कर रही है, जैसा कि अनुप्रति कोचिंग योजना जैसे कार्यक्रमों से स्पष्ट है, जो मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कोचिंग के लिए प्रोत्साहित करती है।

यह स्थिति एक विरोधाभास को जन्म देती है: सरकार एक ओर कोचिंग उद्योग को नियंत्रित करने के लिए विधेयक ला रही है, वहीं दूसरी ओर मुफ्त कोचिंग योजनाओं के माध्यम से इसे बढ़ावा भी दे रही है। कोटा में कई कोचिंग संस्थानों ने सर्वे किए, जिनमें 40 प्रतिशत अभिभावकों ने कोटा को महंगा और 35 प्रतिशत ने आत्महत्याओं के कारण असुरक्षित बताया। फिर भी, कोचिंग संस्थान टॉपर्स और रिजल्ट्स के दम पर अपनी साख बनाए रखते हैं। सीकर में कोचिंग उद्योग ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया है, जहाँ 5,000 से अधिक फैकल्टी और लाखों छात्र इस उद्योग का हिस्सा हैं। लेकिन इस चमक के पीछे मानसिक दबाव, तनाव, और आत्महत्याओं का अंधेरा सच भी छिपा है। मानसिक स्वास्थ्य इस उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती है। कोटा में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। 2023 में 23 छात्रों की आत्महत्या के बाद, प्रशासन ने मनोरंजक गतिविधियों को अनिवार्य किया और दो महीने तक टेस्ट न लेने का आदेश दिया। इसके अलावा, K-SOS (Kota-Safety of Students) ऐप में पैनिक बटन और हेल्पलाइन नंबर (18002333330, 1800914416) जैसी सुविधाएँ शुरू की गई हैं।

जयपुर और सीकर जैसे शहरों में भी कोचिंग सेंटरों में काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। फिर भी, ये उपाय केवल सतही हैं, क्योंकि मूल समस्या अत्यधिक दबाव और असफलता का डर अभी भी बरकरार है। हालांकि सरकार के नियामक प्रयास इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं। राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक–2025 में कई प्रावधान शामिल हैं, जैसे पंजीकरण अनिवार्य करना, फीस को चार किस्तों में लेना, और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक। केंद्र सरकार की नौ सदस्यीय समिति, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी की अध्यक्षता में, कोचिंग पर निर्भरता कम करने और डमी स्कूलों की समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है। लेकिन इन प्रयासों का प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती है, क्योंकि कोचिंग संस्थान आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। इस स्थिति का समाधान केवल नियमन से संभव नहीं है। स्कूली शिक्षा में सुधार, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना, शिक्षकों का प्रशिक्षण, और आधुनिक पाठ्यक्रम लागू करना आवश्यक है। साथ ही, समाज को यह समझने की जरूरत है कि शिक्षा केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के समग्र विकास का आधार है। अभिभावकों को बच्चों पर अत्यधिक दबाव डालने से बचना होगा, और सरकार को कोचिंग के बजाय स्कूलों को सशक्त बनाने पर ध्यान देना होगा।कोचिंग उद्योग का विस्तार राजस्थान के छोटे–बड़े शहरों में शिक्षा की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को दर्शाता है।

यह उद्योग न केवल आर्थिक अवसर सृजित करता है, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ भी पैदा करता है। कोटा, जयपुर, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, और भरतपुर जैसे शहरों में कोचिंग सेंटरों की बाढ़ ने शिक्षा को एक व्यवसाय में बदल दिया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम मानसिक दबाव, आत्महत्याएँ, और डमी स्कूलों का चलन हमारे सामने एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सरकार और समाज को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा, ताकि शिक्षा फिर से अपने मूल उद्देश्य ज्ञान और नैतिकता के प्रसार को प्राप्त कर सके।

–राजेन्द्र मोहन शर्मा,
वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद् एवं चिन्तक

राशिफल

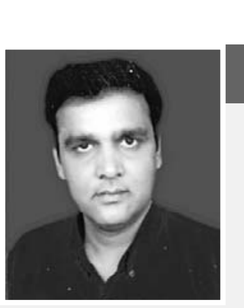

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 30 जून, 2025

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, मघा नक्षत्र प्रात: 7:21 तक, सिद्धि योग सायं 5:20 तक, बालव करण प्रात: 9:24 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मिथुन, चन्द्रमा–सिंह, मंगल–सिंह, बुध–कर्क, गुरू–मिथुन, शुक्र–वृष, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से प्रात: 7:21 तक है। रवियोग प्रात: 7:21 से आरम्भ होगा। आज स्कन्ध पंचमी, द्वारकाधीश पाटोत्सव, कुमार षष्ठी, हेरा पंचमी है। आज साँई टेऊराम जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:22 तक, शुभ 9:05 से 10:48 तक, चर 2:13 से 3:55 तक, लाभ–अमृत 3:55 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:20

मेष
परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

वृष
घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

कर्क
आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज वर्तमान में चल रहा मानसिक तनाव दूर होगा।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय बना रहेगा। अनावश्यक धन खर्च होगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

धनु
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को परेशानी अभी यथावत बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कुंभ
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन
स्वास्थ्य से संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी।